सांध्य दैनिक
4PM
जिद...सच की
www.4pm.co.in www.facebook.com/4pmnewsnetwork @Editor_Sanjay YouTube @4pm NEWS NETWORK
● वर्ष: 10 ● अंक: 170 ● पृष्ठ: 8 ● लखनऊ, गुरुवार, 25 जुलाई, 2024
मूल्य ₹ 3/-

अतीत पे ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण पे केन्द्रित करो।

-गौतम बुद्ध

महिलाओं पर ओछी टिप्पणी करना सीएम... 7
हरियाणा में अपने ही रच रहे भाजपा... 3
ममता का एकल पीठ के आदेश... 2

यूपी विधानसभा में योगी के सामने दोहरी चुनौती

» 29 जुलाई से शुरू हो रहा मानसून सत्र, हंगामेदार होने के आसार
» विपक्ष के साथ सहयोगी भी खड़ी करेंगे भाजपा के लिए मुश्किलें
» सहयोगियों ने योगी सरकार पर ही उठाए सवाल
» पार्टी में भी जारी है आंतरिक कलह, योगी-केशव आमने-सामने

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अंदर लगातार उठापटक मची हुई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच लगातार चूहे-बिल्ली का खेल जारी है। लोकसभा नतीजों की समीक्षा के लिए हुई बैठकों में जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन को सरकार से ऊपर बताया था, उसके बाद से ही दोनों के बीच तल्खियों की खबरों को हवा मिल गई थी। साफ है प्रदेश भाजपा में सरकार बनाम संगठन और योगी के सामने केशव का खेल लगातार जारी है।

केशव कुछ दिनों से काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। सहयोगी दल व पार्टी के विधायक और सरकार के मंत्री भी केशव से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अब मुख्यमंत्री योगी भी पार्टी विधायकों व मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। पार्टी में मची सरगरमी इसलिए भी अहम है क्योंकि 29 जुलाई से यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, तो वहीं प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होना है। ऐसे में कहीं न कहीं उपचुनाव के नतीजे सीएम योगी के भविष्य का फैसला जरूर करेंगे। वहीं विधानसभा में भी योगी सरकार के सामने विपक्ष के साथ-साथ अपनों की भी चुनौतियां होंगी। सभी की नजरें 27 जुलाई को दिल्ली में होने वाली बैठक पर टिकी हैं। जहां नीती आयोग की बैठक के बाद पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ यूपी के मुद्दे पर बैठक होनी है। जिसमें सीएम योगी और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के मौजूद रहने की संभावना है।

अनुप्रिया, निषाद और जयंत ने दिखाए तेवर

लोकसभा चुनाव में हार के बाद सबसे पहले अपना दल सोनेलाल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने योगी सरकार को घेरते हुए सरकारी नौकरियों में भेदभाव करने का आरोप लगाया था। उन्होंने चिट्ठी लिखते हुए दावा किया कि पिछड़े और दलित वर्ग के युवाओं को नॉट सूटेबल कहकर भेदभाव किया जा रहा है जिससे उन्हें नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिल पर रहा है। अपना दल इस मुद्दे को लेकर अपने स्टैंड पर कायम हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की दूसरी सहयोगी निषाद पार्टी और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने भी बुलडोजर को लेकर सरकार पर सवाल उठाते हुए घेरने की कोशिश की। उनका आरोप है कि अधिकारी इतने बेलगाम हो गए हैं कि वो मंत्रियों की भी नहीं सुनते हैं। उन्होंने कहा कि जब वो ऐसा करते हैं तो इसका असर चुनावों पर पड़ता है। इसके चलते कार्यकर्ताओं में नाराजगी रहती है। इधर, जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल भी कांवड़ मार्ग पर दुकानों के सामने नाम लिखने के फैसले पर अपनी आपत्ति दर्ज करा चुकी है।

सत्र में सहयोगियों पर भी होगी नजर

उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र 29 जुलाई से शुरू हो रहा है। इस बार सदन में योगी सरकार की राह उतनी आसान होने वाली नहीं है। जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव में जीत के बाद सपा के हौसले बुलंद हैं तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सहयोगी दलों पर भी सबकी नजरें टिकी है जो चुनाव के बाद से ही प्रदेश सरकार पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी की आपसी कलह के बीच अपना दल सोनेलाल, निषाद पार्टी और आरएलडी भी अलग-अलग मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार को घेरने में पीछे नहीं है। देखना होगा कि विधानसभा सत्र में भी क्या इनके तेवर ऐसे ही दिखाई देंगे या नहीं। इस बार विपक्ष के साथ सहयोगी दलों पर भी अपने पक्ष को रखने का दबाव होगा। अगर वो अपने मुद्दे मजबूती से नहीं रखते हैं तो इसका असर उनके वोटबैंक पर पड़ेगा। लेकिन, अगर वो सरकार को घेरेंगे तो गठबंधन का तालमेल बिगड़ता दिखाई दे सकता है।

सीएम केजरीवाल को राहत नहीं

» सीबीआई मामले में कोर्ट ने 8 अगस्त तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को फिर बढ़ा दिया है। अब आठ अगस्त को मामले की सुनवाई होगी। तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केजरीवाल की पेशी हुई। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल से ही गिरफ्तार किया था।

सीएम केजरीवाल के अलावा पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के कविता की भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी हुई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया और के कविता की न्यायिक हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। केजरीवाल को विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया था। वह अपनी न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर सीबीआई और ईडी मामलों के सिलसिले में पेश हुए थे।

आप को मिला नया ठिकाना

दिल्ली में आम आदमी पार्टी को नया ठिकाना मिल गया है। केंद्र सरकार ने पार्टी दफ्तर के लिए जगह अलॉट कर दी है। जानकारी के मुताबिक, आप के राष्ट्रीय कार्यालय का नया पता अब बंगला नंबर-1, रविशंकर शुक्ला लेन होगा। यहीं से पार्टी की सभी गतिविधियां संचालित होंगी। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद आप को नया कार्यालय अलॉट किया है। इससेपहले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के सामने डेडलाइन तय की थी और जगह देने का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट का कहना था कि अब और वक्त नहीं दिया जा सकता है। 25 जुलाई तक इस मामले में फैसला लिया जाए। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने आप को राउज एवेन्यू में स्थित मौजूदा दफ्तर खाली करने का निर्देश दिया है।

केंद्र सरकार को लगा 'सुप्रीम' झटका

» कोर्ट बोला- राज्यों को खदानों और खनिजों वाली भूमि पर टैक्स लगाने का अधिकार
» सीजेआई की मौजूदगी वाली 9 जजों की पीठ ने 8-1 के बहुमत से सुनाया फैसला
» जस्टिस बीवी नागरत्ना का फैसला अलग

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। सर्वोच्च अदालत से केंद्र सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ ने 8-1 के बहुमत से फैसला सुनाया कि संविधान के तहत राज्यों को खदानों और खनिजों वाली भूमि पर कर यानी टैक्स लगाने का अधिकार है।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि निकाले गए खनिज पर देय रॉयल्टी कोई कर नहीं है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सात अन्य जजों के साथ बहुमत से फैसला सुनाया, जबकि जस्टिस बीवी नागरत्ना ने असहमति जताते हुए इनके खिलाफ फैसला सुनाया।

सीजेआई ने सुनाया बहुमत का फैसला

बहुमत के फैसले के ऑपरेटिव हिस्से को पढ़ते हुए, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि शीर्ष अदालत की सात-न्यायाधीशों की संविधान पीठ का 1989 का फैसला, जिसमें कहा गया था कि रॉयल्टी एक कर है, गलत है। शुरू में सीजेआई ने कहा कि पीठ ने दो अलग-अलग फैसले सुनाए हैं और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने इस मामले में अन्य जजों से अलग असहमतिपूर्ण विचार दिए हैं।

राज्यों के पास खदानों पर कर लगाने की विधायी क्षमता नहीं : नागरत्ना

वहीं अपना फैसला पढ़ते हुए न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि राज्यों के पास खदानों और खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने की विधायी क्षमता नहीं है। पीठ ने इस बेहद विवादास्पद मुद्दे पर फैसला किया कि क्या खनिजों पर देय रॉयल्टी खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत एक कर है, और क्या केवल केंद्र को ही इस तरह की वसूली करने की शक्ति है या राज्यों को भी अपने क्षेत्र में खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने का अधिकार है। हालांकि, बहुमत न होने की वजह से उनका फैसला लागू नहीं हो सका।

ममता का एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध

राज्यपाल मानहानि मामले में मुख्यमंत्री ने लगाई गुहार

पीठ ने ममता व तीन अन्य पर गवर्नर के खिलाफ गलत बयान देने पर लगाई है रोक

» सीएम के वकील ने कहा- ममता ने नहीं की राज्यपाल के खिलाफ कोई टिप्पणी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल सीवी आनंद बोस और प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच लगातार तलवारें खिंची रहती हैं। जबसे राज्यपाल यौन उत्पीड़न के आरोपों में घिरे हैं तबसे दोनों के बीच खाई और भी गहरी हो गई। इस बीच अब प्रदेश की मुखिया ममता बनर्जी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ का रुख कर एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। दरअसल, एकल पीठ ने सीएम ममता बनर्जी और तीन अन्य पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ मानहानिकारक और गलत बयान देने पर रोक लगा दी थी।

जिस पर ममता के वकील एस.एन. मुखर्जी ने न्यायमूर्ति आई.पी. मुखर्जी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष कहा कि सीएम ममता बनर्जी ने राज्यपाल के

खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की। वकील ने कहा कि उनकी जिस टिप्पणी की बात हो रही है वह दो नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण के संबंध में सार्वजनिक दायित्व निभाने से जुड़ी है।

शरण देने संबंधी ममता की टिप्पणी पर बांग्लादेश ने जताया विरोध

बांग्लादेश के लोगों को शरण देने संबंधी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हालिया टिप्पणी को लेकर ढाका ने राजनयिक माध्यमों से भारत को अपनी नाखुशी अवगत कराया है और कहा कि उनकी टिप्पणियों से भ्रम पैदा हो सकता है और लोग गुमराह हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक, बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने राजनयिक माध्यम से भारत सरकार से संपर्क किया है और कहा कि बनर्जी की टिप्पणी से लोगों में भ्रम पैदा हो सकता है। विदेश मंत्री हसन महमूद ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से पूरे सम्मान के साथ मै कहना चाहूंगा कि उनके साथ हमारे बेहद अच्छे संबंध हैं। हमारे बीच गहरे संबंध हैं, लेकिन उनकी टिप्पणियों से कुछ हद तक भ्रम की स्थिति पैदा हुई है और इससे लोग गुमराह हो सकते हैं। हमने इस मुद्दे पर भारत सरकार को एक पत्र लिखा है। हाल ही में कोलकाता में एक रैली में बनर्जी ने कहा था कि बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा के मद्देनजर वह पड़ोसी देश से परेशान लोगों के लिए अपने राज्य के दरवाजे खुले रखेंगी और उन्हें शरण देंगी। उन्होंने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर भी इसी तरह की टिप्पणियां पोस्ट कीं।

ममता की अपील पर कोर्ट करेगा सुनवाई

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से कहा गया कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने समाचारों का हवाला दिया है, लेकिन उन्होंने मानहानि मामले में प्रकाशनों को पक्षकार नहीं बनाया है। पीठ ने कहा कि मामले पर सुनवाई होगी जब बोस के वकील अपनी दलीलें पेश करेंगे। न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने तृणमूल कांग्रेस के दो नवनिर्वाचित विधायकों सयंतिका बनर्जी और रेयात हुसैन सरकार के शपथ ग्रहण पर विवाद से संबंधित एक प्रशासनिक बैठक के दौरान कुछ टिप्पणी करने के लिए बनर्जी और तीन अन्य के खिलाफ राज्यपाल द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे पर 16 जुलाई को अंतरिम आदेश पारित किया था। पीठ ने उनपर रोक लगाने का आदेश पारित किया था, जो 14 अगस्त तक लागू रहेगा। यह आदेश दो विधायकों और टीएमसी नेता कुणाल घोष पर भी लागू होगा।

भाजपा ने प्रसिद्ध धामों पर किया कुठाराघात : कांग्रेस

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

ऋषिकेश। श्री केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा ऋषिकेश के कबीर चौरा आश्रम से शिवपुरी के लिए रवाना हुई। यात्रा शुरू होने से पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन महरा ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान माहरा ने प्रदेश सरकार पर कई आरोप लगाए।

केदारनाथ धाम को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि केदारनाथ धाम की प्रतिष्ठा और सम्मान की रक्षा के लिए कांग्रेस ने हरकी पैड़ी से पद यात्रा शुरू की। इसी दिन मुख्यमंत्री ने भी केदारनाथ धाम पहुंच कर दर्शन किए। केदारनाथ धाम से शिला ले जाकर नई दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का शिलान्यास को लेकर भाजपा नेताओं को बाबा केदार से माफी मांगनी चाहिए। दसौनी ने जारी बयान में कहा कि केदारनाथ धाम के नाम से नई दिल्ली में मंदिर के भूमि पूजन से लोगों की धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचा। सत्ता में रहते हुए भाजपा ने प्रसिद्ध धामों पर कुठाराघात करने का काम किया है। केदारनाथ धाम से सोना चोरी को लेकर बीकेटीसी भी विवादों में है। इस पर सवाल उठाने वाले शंकराचार्यों को भी अपमानित किया जा रहा है।

फंड के लिए अजित और गिरीश महाजन में हुई बहस : राउत

» शिवसेना नेता का दावा- अजित बोले क्या जमीन बेचकर दें पैसा

» सरकार की ओर से किसी भी तरह की बहस को किया गया खारिज

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

मुंबई। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर धीरे-धीरे सियासी पारा चढ़ने लगा है। इस बीच शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने दावा किया कि राज्य मंत्रिमंडल की एक बैठक में फंड आवंटन को लेकर वित्त मंत्री अजित पवार और उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी गिरीश महाजन के बीच बहस हुई।

राउत ने कहा कि बीजेपी नेता गिरीश महाजन अपने ग्रामीण विकास विभाग के लिए फंड की मांग कर रहे थे। अजित पवार

हमारे बीच नहीं हुआ कोई विवाद : उदय सामंत

उद्योग विभाग का प्रभार संभाल रहे उदय सामंत ने कहा कि हमारे बीच इस तरह के विवाद नहीं होते। कल कोई विवाद नहीं हुआ। राज्य के आबकारी मंत्री देसाई ने कहा कि कैबिनेट की बैठक हल्के-फुल्के माहौल में हुई। देसाई ने कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। कैबिनेट में फैसले सामूहिक रूप से लिये जाते हैं। टकराव होने का कोई सवाल ही नहीं है।

ने उनसे कहा कि क्या उन्हें महाराष्ट्र की जमीन बेचकर उन्हें धन देना चाहिए। हालांकि, बैठक में मौजूद रहे शिवसेना के मंत्री उदय सामंत और शंभूराज देसाई ने राउत के दावे को खारिज कर दिया।

सूचना विभाग में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों में 75 फीसदी से अधिक ओबीसी

» योगी सरकार ने दिया डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की चिट्ठी का जवाब

» 676 कर्मचारियों में से 512 रिजर्व वर्ग से

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। यूपी भाजपा में मची कलह के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आउटसोर्सिंग और संविदा पर भर्ती किए गए कर्मचारियों की संख्या और उनमें आरक्षण के नियम का पालन किए जाने की जानकारी मांगी थी, जिसके आंकड़े सामने आने शुरू गए हैं। यूपी में अभी सूचना विभाग में आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों के आंकड़े सामने आए हैं जिनमें 676 कर्मचारियों में से 512 कर्मचारी रिजर्व वर्ग से हैं।

केशव मौर्य ने नियुक्ति और कार्मिक विभाग को चिट्ठी लिखकर जानकारी मांगी थी। इस संबंध में सूचना विभाग की ओर से आंकड़े जारी किए है।

इन आंकड़ों के मुताबिक सूचना विभाग में उनके पास आउटसोर्सिंग द्वारा कुल 676 कर्मचारी हायर किए गए हैं। इनमें से 512 कर्मचारी रिजर्व कोटे के हैं। वहीं 340 कर्मचारी ओबीसी वर्ग से आते हैं जो 75 फीसद से भी अधिक हैं।

केशव मौर्य ने की थी मांग

ये तब है जब अभी तक आउटसोर्सिंग में आरक्षण का नियम नहीं लागू किया गया है। बड़ी बात ये है कि आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को शासन स्तर पर भर्ती नहीं किया जाता है बल्कि इनकी भर्ती सीधे विभाग द्वारा हायर की गई एजेंसियों के द्वारा की जाता है। ये आंकड़े इसलिए भी अहम हो जाते हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने संविधान और आरक्षण के मुद्दे को जोर-शोर से उठाया था। जो बीजेपी की हार का एक बड़ा कारण बना।

14 जुलाई को ही लिखी थी चिट्ठी

लोकसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी में जो खींचतान मची हुई है उसके बीच हाल ही में डिप्टी सीएम केशव प्राण मौर्य की एक चिट्ठी वायरल हुई थी, जिसमें उन्होंने कार्मिक विभाग से आउटसोर्सिंग पर भर्ती किए गए कर्मचारियों के आंकड़े और आरक्षण के नियम का पालन किए जाने की जानकारी मांगी थी। ये चिट्ठी 14 जुलाई को बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के अगले दिन ही लिखी गई थी।

भाजपा सांसद कंगना के निर्वाचन को दी गई चुनौती

» उच्च न्यायालय ने जारी किया नोटिस, 21 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का आदेश

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

शिमला। भाजपा सांसद व अभिनेत्री कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्योंकि कंगना को कोर्ट से नोटिस जारी हुआ है। दरअसल, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने किन्नौर के एक निवासी द्वारा दायर याचिका पर भाजपा सांसद कंगना रनौत को नोटिस जारी किया है। याचिका में मंडी से सांसद कंगना के निर्वाचन को रद्द करने का अनुरोध करते हुए दलील दी गई है कि इस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए याचिकाकर्ता के नामांकन पत्र को कथित रूप से गलत तरीके से खारिज कर दिया गया था।

नोटिस जारी करते हुए न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल ने रनौत को 21 अगस्त तक जवाब

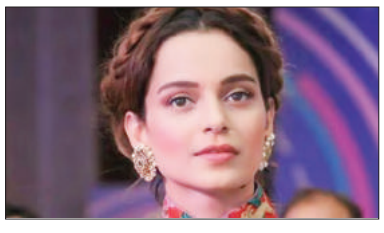

दाखिल करने का निर्देश दिया। रनौत ने मंडी लोकसभा सीट से अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह को 74,755 मतों के अंतर से हराकर जीत हासिल की थी। उन्हें सिंह के 4,62,267 मतों के मुकाबले 5,37,002 मत मिले थे। रनौत के निर्वाचन को रद्द करने की मांग करते हुए याचिकाकर्ता लायक राम नेगी ने कहा कि उनके नामांकन पत्र को निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त, मंडी) ने गलत तरीके से रद्द कर दिया और उन्हें भी पक्षकार बनाया गया है।

हरियाणा में अपने ही रच रहे भाजपा के लिए 'चक्रव्यूह'

बीजेपी सांसद ने ही प्रदेश सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप

सीएम नायब सिंह सैनी को पत्र लिखकर की सीबीआई जांच की मांग

- कांग्रेस बीजेपी सरकार के खिलाफ चला रही 'हरियाणा मांगे हिसाब' अभियान
- भाजपा के सांसद-विधायक लगातार अपनी ही सरकार पर लगा रहे आरोप
- बीजेपी सांसद ने ही सीएम की बढ़ाई मुश्किलें
- मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर दी जानकारी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। हरियाणा में इसी साल आने वाले महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसलिए यहां सियासी पारा काफी हाई है और राजनीतिक हलचल तेज है। भाजपा और कांग्रेस समेत प्रदेश के क्षेत्रीय दल भी अपनी-अपनी तैयारियों में लगे हैं और अपने-अपने समीकरण साधने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार प्रदेश की सत्ता पर बैठी बीजेपी के लिए आगे की राह काफी कठिन नजर आ रही है। क्योंकि प्रदेश में भाजपा के खिलाफ माहौल बना हुआ है। तो वहीं पार्टी के अंदर मची अंदरूनी कलह भाजपा की स्थिति को और भी डामाडोल बना रही है। यही कारण है कि कांग्रेस प्रदेश में दिन पर दिन मजबूत स्थिति में पहुंचती दिख रही है।

दरअसल, हरियाणा में भाजपा के लिए कांग्रेस तो चुनौती खड़ी कर ही रही है, लेकिन उसके अपने भी उसकी लंका लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आए दिन बीजेपी के अंदर से ही सरकार विरोधी आवाजें उठ रही हैं, जिनको मुद्दा बनाकर कांग्रेस बीजेपी पर और भी हावी हो रही है। यही कारण है कि विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच भाजपा के लिए उसके अपने ही नेता मुसीबत खड़ी करते दिख रहे हैं। पिछले कुछ वक्त से केंद्रीय मंत्री और गुरुग्राम से भाजपा के सांसद राव इंद्रजीत सिंह अपनी ही पार्टी व सरकार पर हमलावर हुए पड़े हैं। अब एक बार फिर राव इंद्रजीत सिंह ने हरियाणा की नायाब सैनी सरकार पर सवाल खड़े करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने हरियाणा की भाजपा सरकार पर भ्र?टाचार करने का शक जताया है। इतना ही नहीं बीजेपी सांसद ने इन आरोपों पर सीबीआई जांच की भी मांग की है। उन?होंने मुख?यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखा है।

अपनी पार्टी के नेता द्वारा लगाए गए इन गंभीर आरोपों के चलते अब प्रदेश की नायब सिंह सैनी सरकार और भी दबाव में आ गए हैं। राव इंद्रजीत सिंह ने यह मांग ऐसे समय की है जब हरियाणा के मुख?यमंत्री नायब सिंह सैनी कांग्रेस को भ्र?टाचार की जननी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि 2014 से पहले हरियाणा में भ्र?टाचार का बोलबाला था। लेकिन अब जब भाजपा के ही सांसद अपनी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, तो सीएम नायब सिंह सैनी खुद सवालों के घेरे में आ गए हैं। उधर, प्रदेश में 'हरियाणा मांगे हिसाब' नाम से अपना चुनावी अभियान चला रही कांग्रेस ने राव इंद्रजीत सिंह के कदम पर चुटकी ली है।

राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम की इको ग्रीन कंपनी को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखा है। पत्र में राव इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि इको ग्रीन कंपनी के कारण गुरुग्राम के लोगों को कई सालों तक मुश्किलें हुईं। राज्य सरकार के तमाम निर्देशों के बावजूद कंपनी के कामकाज में किसी तरह का कोई सुधार नहीं हुआ। बता दें कि इको ग्रीन कंपनी की जिम्मेदारी गुरुग्राम नगर निगम के अंतर्गत आने वाले हर घर से कूड़ा इकट्ठा करने की थी। हालांकि, कंपनी के खिलाफ शिकायतें मिलने के बाद हाल ही में इस कंपनी की जगह कूड़ा उठाने का काम दूसरी कंपनी को दे दिया गया था। राव इंद्रजीत सिंह ने अपने पत्र में कहा है कि इस कंपनी को साढ़े तीन सौ करोड़ रुपए दिए गए, जबकि कंपनी ने टेंडर में जो शर्तें थी, उनका पालन नहीं किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस मामले में सीबीआई से जांच कराने की मांग की है।

सरकार, अफसरों और इको ग्रीन कंपनी के बीच मिलीभगत : राव

मुख्यमंत्री सैनी को लिखे गए अपने पत्र में राव इंद्रजीत सिंह ने इस मामले में गुरुग्राम नगर निगम के कई पार्षदों की शिकायत का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि इको ग्रीन कंपनी को एग्रीमेंट से तीन गुना ज्यादा भुगतान किया गया और ऐसा 2019 से 2023 तक किया गया। दक्षिणी हरियाणा के दिग्गज नेता राव इंद्रजीत सिंह ने अपने पत्र में कहा है इस कंपनी को 350 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया जबकि कंपनी ने कोई काम नहीं किया। राव ने लिखा है कि इससे पता चलता है कि सरकार, अफसरों और इको ग्रीन कंपनी के बीच जबरदस्त मिलीभगत है।

कांग्रेस को मिला भाजपा को घेरने का मौका

रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने राव इंद्रजीत सिंह के द्वारा मुख्यमंत्री सैनी को लिखे गए पत्र को लेकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टिप्पणी की है। हुड्डा ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि एक ओर हरियाणा से केंद्रीय मंत्री व वरिष्ठ भाजपा सांसद गुरुग्राम में मौजूदा सरकार-प्रशासन द्वारा किए गए 350 करोड़ के घोटाले की केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा जांच की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर केंद्रीय जांच एजेंसियां हरियाणा के कांग्रेसी विधायकों को निशाना बनाने में व्यस्त हैं। जाहिर है कि हुड्डा इन दिनों हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और आए दिन भाजपा राज में हुए भ्रष्टाचार को जनता के बीच रखने का काम कर रहे हैं। ऐसे में वह आने वाले दिनों में बीजेपी के नेताओं के बयानों को चुनाव में मुद्दा बना सकते हैं।

बीजेपी के पूर्व मंत्री भी अपनी ही सरकार पर लगा चुके हैं आरोप

बीते रविवार को ही हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह ने भी खुलकर अपनी सरकार को निशाने पर लिया था। राव नरबीर सिंह ने कहा था कि हरियाणा में अधिकारियों ने लूट मचा रखी है। विशेषकर गुरुग्राम में हर काम के लिए अफसर आम लोगों से मोटा पैसा ले रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अफसर बेलगाम हो चुके हैं। सड़कों पर चालान काटकर लूट की जा रही है और तहसील हो या कोई भी सरकारी दफ्तर, सभी जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के नेताओं द्वारा अपनी ही सरकार पर इतने गंभीर आरोप लगाने से कांग्रेस को बीजेपी सरकार के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा मिल गया है।

6 बार के सांसद हैं राव इंद्रजीत सिंह

राव इंद्रजीत सिंह सिर्फ दक्षिणी हरियाणा (अहीरवाल) के ही नहीं पूरे हरियाणा के बड़े नेताओं में शुमार हैं। वह 6 बार सांसद का चुनाव जीत चुके हैं। इनमें से 4 बार वह गुरुग्राम से जीते हैं, जबकि दो बार भिवानी-महेंद्रगढ़ सीट से। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में 11 बार चुनाव लड़ा है और इसमें उन्हें सिर्फ एक बार हार का सामना करना पड़ा है।

पहले भी सरकार को घेर चुके हैं राव

राव इंद्रजीत सिंह दक्षिण हरियाणा के साथ भेदभाव होने की बात राज्य में बीजेपी की सरकार होने के दौरान कई बार कह चुके हैं। मोदी सरकार 3.0 में केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए जाने के बाद से राव इंद्रजीत सिंह काफी नाराज हैं और वह खुलकर कह चुके हैं कि उन्हें इस बार भी मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया। विधानसभा चुनाव में वह इस बार अपनी बेटी आरती सिंह राव को भी लॉन?च करने की तैयारी में हैं।

बजट में हरियाणा की अनदेखी

हरियाणा में भाजपा के लिए सत्ता में वापसी मुश्किल लग रही है। ऐसे में प्रदेश बीजेपी को उम्मीद थी कि चुनावी राज्य के चलते केंद्रीय बजट में हरियाणा को कुछ लाभ दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हरियाणा के लोकसभा चुनाव के नतीजे से संकेत साफ है कि यहां उसे कांग्रेस से जबरदस्त चुनौती मिलने वाली है। ऐसे में यह उम्मीद की जा रही थी कि मोदी सरकार इस चुनावी राज्य पर विशेष नजरें इनायत करेगी लेकिन न जाने सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया?

मिलेनियम सिटी कहा जाता है गुरुग्राम

गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी भी कहा जाता है। पिछले कुछ सालों में यह शहर हिंदुस्तान के नक्शे में एक चमकते शहर के रूप में उभरा है। 2023 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिले आंकड़ों के मुताबिक, गुरुग्राम भारतीय शहरों में इनकम टैक्स देने वाला 9वां सबसे बड़ा शहर है। गुरुग्राम लगभग 10000 करोड़ रुपए का टैक्स देता है और इसका एक चौथाई- आईटी कंपनियों, कंसलटेंसी फर्म आदि से आता है। गुरुग्राम रियल एस्टेट क्षेत्र में भी बड़ी पहचान बना चुका है। साल 2023 में जीएसटी कलेक्शन में भी गुरुग्राम हरियाणा में पहले नंबर पर रहा था। हरियाणा के कुल जीएसटी कलेक्शन में अकेले गुरुग्राम का हिस्सा 40 फीसदी से ज्यादा था। 2023 में हरियाणा का जीएसटी कलेक्शन 10035 करोड़ रुपये था और इसमें गुरुग्राम का हिस्सा 4500 करोड़ से ज्यादा रहा था जबकि पंजाब का कुल जीएसटी कलेक्शन 2,316 करोड़ था।

कांग्रेस ने बजट पर उठाए सवाल

हरियाणा को इस बजट में मोदी सरकार की ओर से कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिलने को कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया है। हरियाणा में विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूरे भाषण में हरियाणा का नाम तक नहीं लिया। राज्य के लोगों को किसी भी तरह की कोई राहत नहीं दी गई। हरियाणा की सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही भाजपा को बजट को लेकर विपक्ष के सवालों का जवाब देना भारी पड़ सकता है। इसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा ने भी सवाल उठाया कि बजट में हरियाणा को कोई नई परियोजना क्यों नहीं दी गई। इसके उलट 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार द्वारा मंजूर की गई बड़ी परियोजनाओं के लिए भी कोई पैसा आवंटित नहीं किया गया।

जिद... सच की

Sanjay Sharma

editor.sanjaysharma
@Editor_Sanjay

बहुत कठिन है डगर केशव की!

भारत की राजनीति का केंद्र कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। वजह है सत्ताधारी दल भाजपा के अंदर मची ऊहापोह। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से यूपी बीजेपी में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक ओर जहां प्रदेश में सरकार और संगठन के बीच विवाद छिड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक-दूसरे के सामने आ गए हैं। हालांकि, केशव प्रसाद मौर्य द्वारा संगठन को सरकार से ऊपर बताने वाले बयान के बाद हाईकमान ने उनकी कुछ लगाम खींची। लेकिन यूपी बीजेपी में मची कलह को उस समय और हवा मिल गई जब केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलकर वापस आए और उसके बाद वो पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आने लगे। पिछले कुछ दिनों से केशव मौर्य से भाजपा के सहयोगी दलों के नेता लगातार मुलाकात कर रहे हैं। साथ ही प्रदेश सरकार के मंत्री व विधायक भी केशव के आगे ही हाजिरी लगा रहे हैं।

ऐसे में अब सवाल ये ही उठता है कि क्या बीजेपी केशव प्रसाद को ओबीसी चेहरे के रूप में आगे कर रही है? क्या लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के पीडीए से मात खाने के बाद अब भाजपा ने केशव प्रसाद मौर्य के कंधों पर ओबीसी की जिम्मेदारी दे दी है और अब वो अखिलेश के पीडीए का हल निकालेंगे? या फिर केशव प्रसाद ये सब दिल्ली के इशारे पर कर रहे हैं। क्योंकि ये तो जग जाहिर है कि सीएम योगी और गुजरात लॉबी के बीच कितने अच्छे संबंध हैं। ऐसे में संभव है कि पार्टी आलाकमान ने खुद सामने न आकर पीछे से ही केशव के कंधे पर हाथ रख दिया हो। जिसका बल पाकर केशव प्रसाद अब पूरे एक्शन में नजर आ रहे हैं। क्योंकि केशव के स्टूल से कुर्सी तक के सफर में लोकप्रियता और समर्थन की कमी एक बड़ी समस्या रहा है। केशव प्रसाद मौर्य खुद अपना भी चुनाव हार गए थे। वहीं लोकसभा में भी उनके सीट खाली करने के बाद उपचुनाव में बीजेपी को पराजय झेलनी पड़ी थी। ऐसे में संभव है कि दिल्ली से केशव प्रसाद को ये कहा गया हो कि वो पार्टी, संगठन और सरकार में अपने पक्ष में समर्थन जुटाकर दिखाएं। तभी उनके स्टूल से कुर्सी तक पहुंचने का सपना साकार हो सकेगा। वर्ना लाख ना चाह कर भी दिल्ली लखनऊ की सत्ता से बाबा को नहीं किनारे लगा पाएगी। वहीं प्रश्न ये भी उठता है कि केशव का लोगों से मिलना और समर्थन जुटाना कहीं बगावत या सपा में जाने का इशारा तो नहीं। ताकि प्रेशर पॉलिटिक्स की दम पर दिल्ली का ध्यान आकर्षित किया जा सके। फिलहाल तो ये सब कयास हैं, लेकिन असल में क्या होना है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा।

“ एक ओर जहां प्रदेश में सरकार और संगठन के बीच विवाद छिड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक-दूसरे के सामने आ गए हैं। हालांकि, केशव प्रसाद मौर्य द्वारा संगठन को सरकार से ऊपर बताने वाले बयान के बाद हाईकमान ने उनकी कुछ लगाम खींची।

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

समावेशी विकास और रोजगार सृजन को प्राथमिकता

सतीश सिंह

बजट में कृषि क्षेत्र को उत्पादन उन्मुख बनाने, रोजगार सृजन में तेजी लाने, निर्माण व विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत बनाने, सेवा क्षेत्र को सबल बनाने, ग्रामीण व शहरी विकास को सुनिश्चित करने, ऊर्जा की क्षमता में इजाफा करने, आधारभूत संरचना को सशक्त बनाने, नवाचार व शोध आदि पर जोर देने के लिए प्रावधान किए गए हैं। नि:संदेह, भारत विकास के मोर्चे पर दुनिया के कई प्रमुख देशों से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। उदाहरण के तौर पर आर्थिक सर्वे में वित्त वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर के 6.5 से 7.0 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है। अमेरिका में वित्त वर्ष 2024-25 में विकास दर के 2.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं, यूरो जोन में वित्त वर्ष 2024-25 में विकास दर के 0.4 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है।

ब्रिटेन में वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान विकास दर के 0.3 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है। हालांकि, चीन में वित्त वर्ष 2024-25 में विकास दर के 5.2 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है। मौजूदा समय में सबसे अधिक संख्या में आयकर देने वाले वेतनभोगी वर्ग हैं। इसलिए, उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए नई कर संरचना का विकल्प चुनने वालों के लिए 7.75 लाख तक की आय को आयकर के दायरे से मुक्त किया जायेगा, जिससे वेतन भोगियों को 17.5 हजार रुपये का लाभ होगा। एनपीएस योजना का लाभ ले रहे कर्मचारियों को और भी फायदा मिल सके, के लिए नियोक्ता के योगदान पर कटौती की सीमा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया है। अब एक लाख रुपये से कम वेतन पाने वाले कर्मचारी, जब कर्मचारी भविष्यनिधि संस्थान में पहली बार खुद को पंजीकृत करेंगे तो उन्हें 15 हजार रुपये की आर्थिक सहायता तीन किस्तों में दी जायेगी। नया रोजगार पाने वाले 30 लाख युवाओं के लिए सरकार एक महीने का भविष्यनिधि अंशदान करेगी, ताकि वे अंशदान देने के लिए प्रोत्साहित हों। सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कर की कटौती सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने की बात बजट में कही है।

इसे एक बहुत ही जरूरी पहल कहा जा सकता है, क्योंकि बुढ़ापे में इंसान को पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने के लिए पूंजीगत खर्च में तेजी लाना बहुत

ही जरूरी है। कोरोना काल से लेकर अभी तक सरकार इस महती कार्य को शिद्दत के साथ कर रही है। इसलिए, पूंजीगत खर्च को बढ़ाने के लिए बजट में 11.11 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस क्रम में ग्रामीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। छह करोड़ किसानों का विवरण लैंड रजिस्ट्री में दर्ज किया जायेगा, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी। पांच राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने की बात भी बजट में कही गई है। किसान क्रेडिट कार्ड ने लाखों किसानों को आत्मनिर्भर बनने में मदद की है। इसलिए, माना जा रहा है कि सरकार की इस पहल से लाखों किसानों को लाभ मिलेगा। बजट प्रावधानों के अनुसार एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक तरीके से खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा, ताकि ज्यादा उत्पादन कम लागत में किया जा सके। बजट प्रावधानों के मुताबिक सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उसके कलस्टर को आगे बढ़ाया जायेगा। उच्च शिक्षा के लिए ऋण लेने वाले छात्रों को घरेलू शिक्षा संस्थान में शिक्षा ग्रहण करने के लिए 10 लाख रुपये का ऋण दिया जायेगा। बजट में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बजट में 5 सालों में 4.1 करोड़ युवाओं को 2 लाख करोड़ रुपये की लागत से रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। युवाओं के लिए मुद्रा ऋण की सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है। इससे, उन्हें कुछ बड़े स्तर पर कारोबार करने में मदद मिलेगी। साथ ही, वे दूसरों को रोजगार देने में समर्थ हो सकेंगे। बजट में 500 शीर्ष कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने की भी बात कही गई है, जिसके तहत इंटर्न को 5,000 रुपये का मासिक भत्ता दिया जायेगा।

इस प्रावधान से युवा कौशलयुक्त बन सकेंगे और उन्हें रोजगार मिलने में आसानी होगी। बजट में 5 सालों में 20 लाख युवाओं को कौशलयुक्त बनाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। इस क्रम में आदर्श कौशल ऋण योजना के तहत युवाओं को 7.5 लाख रुपये का ऋण दिया जायेगा। विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए 3 ऋण गारंटी योजना लाई जायेगी, ताकि अधिक से अधिक संख्या में उद्यमियों को रोजगार मिल सके। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 1 करोड़ परिवारों को आवास प्रदान करने के लिए 10 लाख करोड़ रुपये निवेश किया जाएगा।

हरियाणा के खिलाड़ियों की भागीदारी के अनुरूप ही उम्मीदें

हरियाणा के ओलंपिक पदक विजेताओं की सूची पर नजर डालें तो इनमें से सात पदक अकेले हरियाणा के खिलाड़ियों के नाम हैं। आजादी के 75 साल में यह हरियाणा के लिए बड़ी उपलब्धि है। हरियाणा देश की जनसंख्या का केवल दो प्रतिशत है जबकि खेलों में 20 प्रतिशत से भी अधिक भागीदारी है। खेलों के प्रति हरियाणा के युवाओं का उत्साह निरंतर बढ़ा है। इसका श्रेय हरियाणा में समय-समय पर विभिन्न सरकारों के कार्यकाल में लागू की गई खेल नीति को जाता है।

सतीश मेहरा

पिछले दो दशक से हरियाणा के खिलाड़ियों ने ओलंपिक, राष्ट्रमंडल, एशियाई खेलों के साथ-साथ विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में बेहतर प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन किया है। इस बार भी पेरिस ओलंपिक में पूरे देश की निगाहें हरियाणा-पंजाब के खिलाड़ियों पर लगी हुई हैं। इस ओलंपिक में 117 भारतीय खिलाड़ियों और एथलीटों में 24 खिलाड़ी हरियाणा से हैं और 20 खिलाड़ी पंजाब से हैं। निश्चय ही दोनों प्रदेशों के खिलाड़ी 143 करोड़ भारतीयों की आशा और अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। भारत ने साल 1900 में पेरिस ओलंपिक में पदार्पण किया था। ओलंपिक 1900 से लेकर टोक्यो ओलंपिक 2020 तक भारत ने अब तक 25 ओलंपिक आयोजनों में हिस्सा लिया है। अब तक कुल 1,218 भारतीय एथलीट हिस्सा ले चुके हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 तक भारत ने 35 पदक प्राप्त किये। इनमें 10 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 16 कांस्य पदक शामिल हैं।

छब्बीस जुलाई से शुरू होने वाले पेरिस ओलंपिक में भारत मजबूत दावेदारी के साथ तैयार है। ओलंपिक खेलों में अब तक भारत द्वारा जीते गए कुल पदकों में सबसे ज्यादा 12 मेडल हॉकी टीम के हैं। इनमें आठ गोल्ड, एक सिल्वर और तीन कांस्य पदक हैं। हॉकी के अतिरिक्त 23 पदक भारतीय खिलाड़ियों ने एकल प्रतिस्पर्धाओं में जीते हैं। हरियाणा के ओलंपिक पदक विजेताओं की सूची पर नजर डालें तो इनमें से सात पदक अकेले हरियाणा के खिलाड़ियों के नाम हैं। आजादी के 75 साल में यह हरियाणा के लिए बड़ी उपलब्धि है। हरियाणा देश की जनसंख्या का केवल दो प्रतिशत है जबकि खेलों में 20 प्रतिशत से भी अधिक भागीदारी है। खेलों के प्रति हरियाणा के युवाओं का उत्साह निरंतर बढ़ा है। इसका श्रेय हरियाणा में समय-समय पर विभिन्न सरकारों के कार्यकाल में लागू की गई खेल नीति को जाता है। खेल नीति के तहत वर्तमान में भी पदक लाने वाले युवाओं को करोड़ों के नगद इनाम दिये जाते हैं। साथ ही 'पदक लाओ और पद पाओ' की नीति के तहत पदक विजेताओं को द्वितीय श्रेणी तक के पदों पर नियुक्त किया जाता है।

राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले व पदक पाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। इस नीति के तहत काफी संख्या में खिलाड़ियों को नौकरी दी गई है। प्रदेश के जिन खिलाड़ियों ने ओलंपिक में पदक जीते हैं उनमें 2008 बीजिंग ओलंपिक में विजेंद्र सिंह ने बॉक्सिंग में कांस्य पदक व सुशील कुमार ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता। साल 2012 के लंदन ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ियों में सुशील कुमार ने कुश्ती में रजत पदक, कुश्ती में ही योगेश्वर दत्त ने कांस्य पदक, साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीते वहीं शूटिंग में गगन नारंग ने भी कांस्य पदक जीता।

इसी प्रकार टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता, बजरंग पूनिया और रवि कुमार दोनों ने कुश्ती में कांस्य पदक जीते। पिछले ओलंपिक की तरह इस बार भी पदकों की सबसे ज्यादा दावेदारी हरियाणा की रहने वाली है। पेरिस जाने वाले दल में सबसे अधिक हरियाणा के दो दर्जन खिलाड़ी शामिल हैं। कुश्ती और निशानेबाजी में हरियाणा के छह-छह खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इन दोनों खेलों में सबसे ज्यादा पदकों की आशा है। वहीं, रोइंग, आर्चरी, गोल्फ में एक-एक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। पुरुष हॉकी टीम में भी राज्य के तीन खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। एथलीटों की सूची में सबसे ऊपर नाम ओलंपिक गोल्ड विजेता नीरज चोपड़ा (गोल्डन ब्वॉय) का हैं। नीरज चोपड़ा की अगुवाई में गए भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन और बेहतर रहेगा, क्योंकि स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले स्टार खिलाड़ी उनके साथ हैं। इससे सभी एथलीटों-खिलाड़ियों का मनोबल ऊंचा होगा और वह सभी अपना बेहतर दे पाएंगे। कुश्ती में हरियाणा के छह खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इनमें विनेश फोगाट, अंतिम पंघाल, अंशु मलिक, रितिका हुड्डा, निशा दहिया व अमन सहरावत शामिल हैं। निशानेबाजी में मनु भाकर व रिदम सांगवान तीन अलग-अलग वर्गों में हिस्सा ले रही हैं। इनके अलावा अनीश भानवाला, सरबजोत सिंह, रमिता जिंदल, रेजा ढिल्लों निशानेबाजी में अपना दमखम दिखाएंगे।

बॉक्सिंग में हरियाणा के चार खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इनमें प्रीति पंवार, जैसमीन, अमित पंघाल और निशांत देव शामिल हैं। इन खिलाड़ियों की तैयारियों को देखते हुए देश को उम्मीद है कि बॉक्सिंग में भी देश को पदक की दरकार रहेगी। वहीं, रोइंग में ओलंपिक का पहला कोटा दिलाने वाले बलराज पंवार भी पदक के दावेदार हैं। इसके अलावा एथलेटिक्स में किरण पहल, गोल्फ में दीक्षा डागर, आर्चरी में भजन कौर और पुरुष हॉकी टीम में हरियाणा के तीन खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। बीते दिनों प्रधानमंत्री ने भी शुभकामनाएं देकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया है। सभी खिलाड़ियों और एथलीटों से देश को पूरी उम्मीदें हैं।

गैस-कब्ज या बदहजमी से छुटकारा दिलायेंगे ये टिप्स

गैस-बदहजमी-कब्ज-अपच ये आम समस्याएं हैं। खासतौर से बारिश के मौसम में तो ये और बढ़ जाती हैं। इससे छुटकारा पाना बेहद आसान है। बस अपने लिए कुछ वक्त रोज निकालना होगा।अगर आप पेट की गैस से परेशान हैं और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जो आपकी समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। गैस-कब्ज से आसानी से निजात पाने का सबसे आसान तरीका है वॉकिंग। बहुत पुराने समय से ही लोग वॉक करते आ रहे हैं। वॉकिंग आंतों की गैस रिलीज़ करने और पाचन क्रिया बेहतर बनाने का सबसे आसान और सटीक उपाय है।

वॉकिंग का नया ट्रेंड

अब फार्ट वॉक फिटनेस का नया ट्रेंड बन गया है। यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो ब्लोटिंग, अफारा, बदहजमी, गैस, हार्टबर्न की समस्या से परेशान हैं। हाईफाइबर भोजन के बाद गार्डन या बालकनी में वॉक करने से सेहत पर कमाल का सकारात्मक असर पड़ सकता है।

फार्ट वॉक लाभकारी है

भोजन के बाद की चहलकदमी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए फायदेमंद है। इसे गैसट्रोइंटेसटाइंल ट्रैक्ट भी कहते हैं। फार्ट वॉक से खाना सूक्ष्म टुकड़ों में टूट जाता है और पौष्टिक तत्व हजम हो जाते हैं। साधारण शब्दों फार्ट वॉक जीआई ट्रैक्ट के लिए छोटी सी एक्सरसाइज है।

इस तरह पचता है खाना

फार्ट वॉकिंग पाचन क्रिया को इस तरह से बेहतर बनाती है इससे आंतों में फूड की गतिशीलता बेहतर हो जाती है। फार्ट वॉकिंग से फूड जीआई ट्रैक्ट में अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ता है। अध्ययन से यह भी मालूम होता है कि फार्ट वॉक से गैस्ट्रिक एम्प्टिंग तेज हो जाती है यानी पेट से छोटी आंत तक फूड पहुँचाने की प्रक्रिया गति पकड़ लेती है।

वॉक से शरीर में फंसी गैस बाहर निकल जाती है

पेट में गैस जमा होने का मुख्य कारण ब्लोटिंग है। फार्ट वॉक से शरीर में फंसी गैस रिलीज हो जाती है। वॉकिंग से पेट पर आंतरिक दबाव पड़ता है इससे गैस बाहर निकलने में मदद मिलती है। नर्सिंग ऑफिसर मुकेश लोरा ने बताया रोज़ाना 30 मिनट की वॉक से ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट हो जाता है और इससे टाइप 2 डायबिटीज या इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले व्यक्ति को मदद मिलती है।

वो बातें जो हमें याद रखना है

नर्सिंग ऑफिसर मुकेश लोरा ने बताया खाना खाने के लगभग 40 से 60 मिनट बाद ही फार्ट वॉकिंग शुरू करें। धीरे और आराम से चलें, तेज़ न चलें, क्योंकि इससे बेचैनी हो सकती है। फार्ट वॉक के बाद पर्याप्त मात्रा में पानी पीयें और खुद को हाइड्रेट रखें। अच्छे नतीजे के लिए कम से कम 20 से 30 मिनट की फार्ट वॉक रोज करें।

हंसना मना है

पति शाम को बहुत उदास होकर घर लौटा पत्नी: क्या हुआ जी? **पति:** आज हमारे ऑफिस की बिल्डिंग गिर गई और सारे लोग मर गए। पत्नी: तो आप कैसे बचे? **पति:** मैं सिगरेट पीने बाहर गया हुआ था। **पत्नी:** चलो शुक्र है। भगवान का थोड़ी देर में ही टीवी पर खबर आने लगी कि सरकार ने सभी मृतकों के परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपये देने का फैसला किया है। **पत्नी गुस्से में:** ना जाने तुम्हारी ये सिगरेट की आदत कब छूटेगी।

मरीज: मुझे बीमारी है कि खाने के बाद भूख नहीं लगती,सोने के बाद नींद नहीं आती काम करूं तो थक जाता हूं। डॉक्टर: बहुत गंभीर बीमारी है, एक काम करो, सारी रात धूप में बैठो जल्दी ठीक हो जाओगे।

एक बार सोनू ट्रेन में सफर कर रहा था ट्रेन में बहुत भीड़ होने की वजह से वो एक गंजे आदमी के गोद में बैठ गया। **आदमी (गुस्से में)** - हां, हां! मेरे सिर पर आकर बैठा जा **सोनू** - नहीं, अंकल मैं यहीं ठीक हूं, वहां से फिसल कर गिरने का डर है।

कहानी — जादूगर का घमंड

एक बार राजा कृष्ण देव राय के दरबार में एक जादूगर आया। उसने बहुत देर तक हैरतअंगेज जादू करतब दिखा कर पूरे दरबार का मनोरंजन किया। फिर जाते समय राजा से ढेर सारे उपहार ले कर अपनी कला के घमंड में सबको चुनौती दे डाली-क्या कोई व्यक्ति मेरे जैसे अद्भुत करतब दिखा सकता है। क्या कोई मुझे यहाँ टक्कर दे सकता है? इस खुली चुनौती को सुन कर सारे दरबारी चुप हो गए। परंतु तेनालीराम को इस जादूगर का यह अभिमान अच्छा नहीं लगा। वह तुरंत उठ खड़े हुए और बोले कि हाँ मैं तुम्हे चुनौती देता हूँ कि जो करतब मैं अपनी आँखें बंद कर के दिखा दूंगा वह तुम खुली आंखो से भी नहीं कर पाओगे। अब बताओ क्या तुम मेरी चुनौती स्वीकार करते हो? जादूगर अपने अहम में अंध था। उसने तुरंत इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। तेनालीराम ने रसोइये को बुला कर उस के साथ मिर्ची का पाउडर मंगवाया। अब तेनालीराम ने अपनी आँखें बंद की और उनपर एक मुट्ठी मिर्ची पाउडर डाल दिया। फिर थोड़ी देर में उन्होंने मिर्ची पाउडर झटक कर कपड़े से आँखें पोंछ कर शीतल जल से अपना चेहरा धो लिया। और फिर जादूगर से कहा कि अब तुम खुली आँखों से यह करतब करके अपनी जादूगरी का नमूना दिखाओ। घमंडी जादूगर को अपनी गलती समझ आ गयी। उसने माफी मांगी और हाथ जोड़कर राजा के दरबार से चला गया। राजा कृष्ण देव राय अपने चतुर मंत्री तेनालीराम की इस युक्ति से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होने तुरंत तेनालीराम को पुरस्कार दे कर सम्मानित किया और राज्य की इज्जत रखने के लिए धन्यवाद दिया।

7 अंतर खोजें

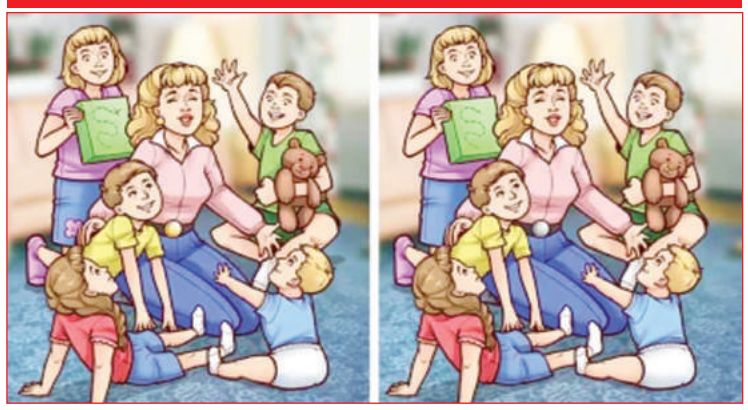

जानिए कैसा रहेगा कल का दिन

पंडित संदीप आत्रेय शास्त्री

लेखक प्रसिद्ध ज्योतिषविद हैं। सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कॉल करें-9837081951

मेष

सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। पार्टनरों का सहयोग मिलेगा। कारोबारी अनुबंधों में वृद्धि हो सकती है। समय का लाभ लें। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी।

वृषभ

व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। आय के नए स्रोत प्राप्त हो सकते हैं। व्यापार-व्यवसाय में लाभ होगा। प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। कीमती वस्तुएं संभालकर रखें।

मिथुन

दूर यात्रा की योजना बन सकती है। मनपसंद भोजन का आनंद प्राप्त होगा। वरिष्ठजनों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। विद्यार्थी वर्ग सफलता अर्जित करेगा। पठन-पाठन में मन लगेगा।

कर्क

व्यवसाय ठीक चलेगा। धन प्राप्ति सुगम होगी। ऐश्वर्य के साधनों पर बड़ा खर्च हो सकता है। जल्दबाजी न करें। कष्ट, भय, चिंता व बेचैनी का वातावरण बन सकता है।

सिंह

भूमि, भवन, दुकान व फैक्टरी आदि के खरीदने की योजना बनेगी। रोजगार में वृद्धि होगी। उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। अपरिचितों पर अतिविश्वास न करें।

कन्या

कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। जोखिम व जमानत के कार्य टालें। दूसरों के झगड़ों में न पड़ें। राज्य के प्रतिनिधि सहयोग करेंगे। स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा।

तुला

प्रयास सफल रहेंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आय के स्रोतों में वृद्धि हो सकती है। व्यवसाय ठीक चलेगा। चोट व रोग से बाधा संभव है। फालतू खर्च होगा।

वृश्चिक

प्रतिद्वंद्विता बढ़ेगी। पारिवारिक चिंता में वृद्धि होगी। आवश्यक वस्तु समय पर नहीं मिलेगी। तनाव रहेगा। वाणी पर नियंत्रण रखें। किसी के व्यवहार से क्लेश हो सकता है।

धनु

कोर्ट व कचहरी के काम अनुकूल होंगे। पूजा-पाठ में मन लगेगा। तीर्थयात्रा की योजना बनेगी। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। व्यवसाय ठीक चलेगा।

मकर

शुभ समाचार मिलेंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे। भाइयों का सहयोग प्राप्त होगा। परिवार के साथ मनोरंजन का कार्यक्रम बन सकता है।

कुम्भ

आय में वृद्धि होगी। प्रसन्नता में वृद्धि होगी। पारिवारिक चिंता बनी रहेगी। रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे। अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। सट्टे व लॉटरी से दूर रहें।

मीन

घर-बाहर सहयोग मिलेगा। अपेक्षाकृत कार्यों समय पर संपन्न होंगे। आय में वृद्धि हो सकती है। अप्रत्याशित खर्च सामने आएंगे। कर्ज लेना पड़ सकता है।

गांधी और अंबेडकर पर राय देकर डर गई थीं जाह्नवी

बॉलीवुड | मसाला

बॉलीवुड स्टार्स अक्सर राजनीति से जुड़े मुद्दे पर कुछ भी बोलने से दूर भागते हैं। वहीं कुछ समय पहले जाह्नवी कपूर ने गांधी-अंबेडकर डिबेट पर अपनी राय रखी। एक्ट्रेस की बात सुन लोगों को काफी हैरानी हुई है। जाह्नवी कपूर के बयान ने काफी सुर्खियां बटोरीं थी। जाह्नवी ने इंटरव्यु में खुलासा किया बयान देने के बाद वह काफी डर गई थीं।

जाह्नवी कपूर ने जब इंटरव्यू में गांधी-अंबेडकर डिबेट पर इतनी गहरी बात बोली तो हर कोई हैरान हो गया था। लोगों का कहना था कि जाह्नवी को इस मुद्दे पर बोलने के लिए उनकी पीआर टीम ने ही ट्रेंड किया होगा। लेकिन ऐसा नहीं था। एक्ट्रेस ने इंटरव्यू में बताया है कि उनकी टीम को तो पता भी नहीं था कि वह इस बारे में कुछ बोल देंगी। एक्ट्रेस बयान देने के बाद पैनिक हो गई थी। उन्हें डर था कि कहीं उनके बयान से कुछ बवाल न मच जाए। जाह्नवी कपूर ने बोला कि उस इंटरव्यू के खत्म होने के बाद मैंने अपने पीआर को देखा कि मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, पीआर टीम ने बोला कि यह बात उठाई जा सकती है लेकिन देखते हैं क्या होगा। मैं घबरा गई थी। उन्हें र था कि बयान की वजह से कहीं फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही की रिलीज को दिक्कत न हो जाए।

इंटरव्यू में जाह्नवी कपूर ने आगे बोला कि मुझे नहीं पता था कि यह सबी बात है या नहीं। मेरे पीआर भी बहुत पैनिक होने लगे थे। पीआर टीम ने बोला कि उस पार्ट को एडिट करा देते हैं हमे फालतू का अटेंशन नहीं चाहिए। पीआरटीम ने पब्लिकेशन से बोला लेकिन उन्होंने इसे एडिट करने से मना कर दिया। ऐसे में जाह्नवी परेशान हो गई थी।

विक्की कौशल के साथ नाम जुड़ने पर नाखुश हुई हरलीन सेठी

विक्की कौशल इन दिनों अपनी फिल्म Bad NeWZ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। विक्की ने अपने 9 साल के करियर में काफी ऊंचा मुकाम हासिल किया है। कई हिट फिल्मों में काम किया और कैटरीना संग शादी के बंधन में बंधे। क्या आप जानते हैं बॉलीवुड में पॉपुलर होने से पहले विक्की कौशल ने हरलीन सेठी को डेट किया था। दोनों अपने रिश्ते में काफी सीरियस थे, फिर अचानक विक्की की पसंद बदल गई। दोनों का ब्रेकअप हो गया। इस ब्रेकअप की वजह से हरलीन काफी टूट गई थी। ब्रेकअप के सालों बाद हरलीन ने विक्की कौशल की एक्स तौर पर पहचाने जाने पर अपना रिएक्शन दिया है।

हरलीन से एक इंटरव्यू में पूछा कि क्या उन्हें कभी अपनी पहचान को लेकर परेशानी हुई है, क्योंकि उन्हें विक्की कौशल की एक्स गर्लफ्रेंड का लेबल दिया गया। हरलीन ने इस सवाल के जवाब में बोला- मेरे इंस्टाग्राम बायो में दो शब्द हैं आई एम... आगे कुछ नहीं है। मुझे किसी भी चीज से खुद को पहचानने जाने में समस्या होती है। मुझे लगता है कि आप अपने जीवन में मिले सभी अनुभव से बने होते हैं। ऐसे में आपको लाइफ में हर इंसान का आभारी होना चाहिए। मैं इसी वजह से इन सभी चीजों का आभार मानती हूं।

बॉलीवुड | मन की बात

इंडस्ट्री में पेमेंट प्रोसेस में है बहुत बड़ा फर्क : तुराज

फिल्म इंडस्ट्री में कलाकारों के बीच पे-पैरिटी या पेमेंट गैप को लेकर अलग ही चर्चा छिड़ी हुई है। पहले तो सिर्फ हीरो और हीरोइन को मिलने वाली कम-ज्यादा फीस पर ही बातें हुआ करती थी, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ गया है। अब बात सिर्फ पेमेंट गैप नहीं बल्कि स्टार्स के टैंटरम पर होने वाले खर्च होने से प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने और सिंगर्स-राइटर्स को मिलने वाली फीस तक पर आ गया है। इस पूरी डिस्कशन पर लिरिसिस्ट ए. एम. तुराज ने भी अपनी राय रखी है। तुराज ने बताया कि इस पेमेंट प्रोसेस में बहुत बड़ा फर्क है। एक्टर्स तो दूर की बात सिंगर्स-राइटर्स के बीच भी बड़ा फर्क है। उनके मुताबिक ये हां या ना के बराबर है जिसे कम शायद किया ही नहीं जा सकता। लेकिन अगर ये ठीक हो जाए तो इंडस्ट्री को और बेहतर बनाया जा सकता है। ए. एम. तुराज बोले- गैप इतना बड़ा है कि हां और ना के बराबर है। इसमें जमीन और आसमान का फर्क है। ये अच्छा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इसमें जिनका नुकसान हो रहा है उनका तो होना ही है। जिनको नहीं मिला उनका तो बहुत है। इसमें एक्टर्स का बड़ा नुकसान है। बड़ा क्रिएशन नहीं हो पा रहा है। फिल्में गिर रही हैं धड़ाधड़। मैं ये कहता हूं कि दीजिए आप 200 करोड़ दीजिए, 500 करोड़ दीजिए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे घर से तो जा नहीं रहे। लेकिन अगर उसका टिकट 5 करोड़ का बिकता है, तो आप उसको 100 करोड़ दे दो। लेकिन वो तो उतना ही बिकता है। तुराज ने सवाल उठाते हुए आगे कहा- जिस आदमी को आपने एक लाख, दो लाख...4 लाख दे दिए...एक-दो करोड़ दे दिए, उतने का ही टिकट उसका भी बिकता है। उतने का ही आपका भी बिकता है। आपका टिकट कोई 5 करोड़ का तो बिकता नहीं है। तो ये फर्क जब वहां टिकट विंडो पर नहीं है तो अंदर क्यों है? ये तो वहां होना चाहिए था। फिर क्यों नुकसान होगा, क्योंकि आप वहां से ले रहे हैं तो इनको दे रहे हैं। लेकिन वहां से उतना ही आ रहा है लेकिन आप इनको ज्यादा दे रहे हैं ये तो ठीक नहीं है।

इसे माना जाता है दुनिया की सबसे खतरनाक डिश, फिर भी थाइलैंड में चाव से खाते हैं लोग

दुनिया में इतनी सारी जगहें हैं और हर जगह का अपना खान-पान है। कुछ जगहों की अपनी खास डिश होती है, जिसे खाने के लिए लोग वहां पहुंचते हैं। सबके अपने स्वाद के मुताबिक अच्छी-अच्छी चीज़ें बनाई जाती हैं। वो बात अलग है कि कुछ ऐसी डिशेज़ भी हैं, जो जुबान को भले ही अच्छी लगें लेकिन सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही खतरनाक डिश के बारे में बताएंगे। ये अजीबोगरीब डिश दक्षिणी एशिया की ही है। ये पकवान इंसान के लिवर पर ऐसा असर करता है कि उसे मौत के मुंहाने तक पहुंचा सकता है। ऑडिटी सेंट्रल वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक ये थाइलैंड की एक खास डिश है, जिसे खाना बेहद रिस्की है। लोग इसके स्वाद को पसंद करते हैं, इसलिए खाते भी हैं, लेकिन इससे उनकी मौत का रिस्क बढ़ जाता है। आपको सुनने में ये बात अजीब लग सकती है लेकिन थाइलैंड में आमतौर पर मिलने वाली इस डिश को खाते ही आपके लिवर में कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। दावा ये भी किया जाता है कि इसकी एक बाइट भी कैंसर को सीधा बुलावा देती है। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ इस डिश की वजह से ही 20 हज़ार लोग हर साल थाइलैंड में मर जाते हैं। बावजूद इसके थाईलैंड के Khon Kaen नाम के प्रोविंस में लोग इसे पसंद भी करते हैं और खाते भी हैं। इस पकवान का नाम कोइ प्ला है। इसके लिए छोटे-छोटे टुकड़ों में कटी हुई कच्ची मछली लेते हैं, जिसे हर्ब्स, स्पाइसेज़ और नींबू के रस को मिलाकर स्वादिष्ट बनाया जाता है। थाइलैंड में लाखों लोग इस पकवान को पसंद करते हैं। मछली लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाती लेकिन इसमें मौजूद परजीवी कीड़े डिश के जरिये लोगों के शरीर में चले जाते हैं और खाने वाले की जान के दुश्मन बन जाते हैं। इससे cholangiocarcinoma यानि बाइल डक्ट कैंसर जैसी बीमारी का चांस बढ़ जाता है। यही वजह है कि इसे दुनिया की सबसे खतरनाक डिश माना जाता है।

अजब-गजब | इसी टीले से जुड़ा है नागवंश का इतिहास

रात को कोई नहीं ले सकता इस मंदिर में एंट्री, आसपास से आती हैं डरावनी आवाजें

मंदिर में पूजा-पाठ करने के कुछ नियम होते हैं। मंदिर में एंट्री से लेकर आरती तक, हर एक समय तय होता है। लेकिन क्या आपने एक ऐसे मंदिर के बारे में सुना है, जहां लोगों को रात को जाने की अनुमति नहीं होती। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के मथुरा में है। न महिला-न पुरुष, कोई भी इस मंदिर में रात को नहीं जा सकता है। यह अनोखा मंदिर रेत के टीले पर बना हुआ है।

मान्यता के अनुसार इस मंदिर में अगर कोई रात को रुकता है, तो उसके साथ अनहोनी हो जाती है। इस टीले पर रात में अजब-गजब आवाज आती है। मथुरा प्राचीन समय से ही मंदिर और टीलों का स्थान रहा है। मथुरा में ऐसे पांच टीले हैं, जो की कृष्ण-कालीन युग से चले आ रहे हैं। इन मिट्टी के टीलों की एक अपनी ही अलग मानता है। मथुरा के सुभाष इंटर कॉलेज के सामने बना है नाग टीला। नाग टीले का इतिहास यहां नाग वंश से जुड़ा हुआ है। टीले के प्रांगण में स्थित है, राधा कृष्ण का मंदिर। यह मंदिर सैकड़ों साल पुराना है। इस मंदिर की अपनी एक अलग

एक पहचान है। मंदिर की मान्यता के बारे में जानकारी देते हुए मंदिर के पुजारी ने बताया कि यहां सैकड़ों साल पुराना मंदिर है। एक मान्यता शुरू से चली आ रही है। मान्यता के अनुसार शाम होते ही किसी स्त्री-पुरुष इस मंदिर में नहीं रुक सकते। मंदिर के पुजारी ने बताया कि यहां जो भी व्यक्ति रुकता है, उसके साथ अनहोनी हो जाती है। टीले के चारों तरफ से अजीबो गरीब आवाज आना शुरू हो जाती है। रात में यह टीला और भी सुनसान हो जाता है।

मंदिर के पुजारी ने यह भी बताया कि इस टीले पर साधु संत और ऋषि-मुनि तपस्या करते थे। यह टीला बहुत ही पवित्र स्थान माना गया है। अगर स्त्री-पुरुष इस टीले पर रात में रुकेंगे तो टीले की मर्यादा और मान्यता दोनों ही खंडित हो जाएगी। कृष्ण कालीन समय से ही इस टीले पर किसी भी महिला या पुरुष का एक साथ रुकना रात्रि में पूर्णतः वर्जित रखा गया है। यह टीला करीब 550 वर्ष पुराना है।

महिलाओं पर ओछी टिप्पणी करना सीएम की आदत : तेजस्वी यादव

» नीतीश कुमार के राजद की महिला विधायक पर भड़कने पर आरजेडी नेता ने किया पलटवार

» तेजस्वी बोले- दुनिया के सबसे बड़े ज्ञाता तो नीतीश ही हैं, उनके अलावा किसी को कुछ नहीं पता

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

पटना। बिहार में इस समय सियासत गरमाई हुई है। एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने हैं। दरअसल, बिहार विधानसभा में मानसून सत्र चल रहा है। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार चर्चा के वक्त एक महिला विधायक पर भड़क गए, जिसको लेकर अब सियासत तेज हो गई है।

सदन में एक चर्चा के दौरान आरजेडी विधायक रेखा पासवान पर विधानसभा में भड़कते हुए नीतीश ने कहा था कि महिला हो, कुछ जानती हो? कहां से आते हैं, इन लोगों ने कुछ किया है? अब इसी को लेकर राजद नेता तेजस्वी यादव की ओर से पलटवार किया गया है। पूर्व उपमुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि महिला हो कुछ जानती हो? महिलाओं पर ओछी, गैर वांछित, असभ्य, अशिष्ट एवं निम्नस्तरीय टिप्पणियां करना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आदत में शुमार हो चुका है। प्रदेश के लिए यह अत्यधिक गंभीर व चिंतनीय विषय है।

कुछ दिन पूर्व बीजेपी महिला विधायक पर भी की थी टिप्पणी

पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पूर्व आदिवासी वर्ग की भाजपा की महिला विधायक पर भी सुंदरता संबंधित भद्दी टिप्पणी की थी। आज अनुसूचित जाति की दो बार से महिला विधायक रेखा पासवान जी पर टिप्पणी की। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सृष्टि के सबसे बड़े ज्ञाता, ध्याता, व्याख्याता और रचयिता तो आदरणीय नीतीश जी बन चुके है, इनको छोड़ कर किसी को कुछ पता नहीं, किसी को कुछ आता-जाता नहीं।

हमने काम किया है, तो हम सुनाएंगे ही : नीतीश

नीतीश ने राजद विधायक रेखा देवी पर भड़कते हुए कहा कि अरे महिला हो, कुछ जानती हो। चुपचाप रहो। इसके बाद उन्होंने राजद पर भी उन्होंने निशाना साधा था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इन लोगों ने कभी भी महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाया है। 2005 के बाद जब हम सत्ता में आए तभी से बढ़ना शुरू किए हैं। इसलिए कह रहे हैं चुपचाप सुनो। इतना ही नहीं मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हम तो सुनाएंगे, अगर आप नहीं सुनेंगे तो यह आपकी गलती है। हमने काम किया है तो हम सुनाएंगे भी। दरअसल, नीतीश कुमार विधानसभा में बोलने के लिए खड़े हुए थे इस दौरान विपक्ष आरक्षण को लेकर हंगामा कर रहा था। नीतीश बार-बार विपक्ष के विधायकों से अपनी बात सुनने की अपील कर रहे थे। लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी था। इसी को लेकर नीतीश कुमार भड़क गए। अपने बयान में उन्होंने यह भी कहा कि सर्वसम्मति से जातीय गणना हुई थी और पिछड़ों की संख्या ज्यादा आई तो हमने 50 फीसदी आरक्षण सीमा को बढ़ाकर 75 फिसदी कर दिया।10 फिसदी केंद्र सरकार ने अपर कास्ट को लागू किया था। उसको भी हमने लागू किया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि हम लोगों ने हर परिवार की आर्थिक स्थिति की जानकारी भी ली है।

पुलिस की मौजूदगी में कांवड़ियों ने ई-रिक्शा को तोड़ा

» चालक की जमकर की धुलाई

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

हरिद्वार। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में कांवड़ियों ने पुलिस की मौजूदगी में डंडों से हमला कर एक ई-रिक्शा को तोड़ दिया और चालक को जख्मी कर दिया। अधिकारियों की ओर से यह जानकारी दी गई। कांवड़ियों

के समूह ने संजय कुमार और वाहन पर इसलिए गुस्सा निकाला क्योंकि उसने उनमें से एक को टक्कर मार दी थी। हालांकि कांवड़िए को कोई चोट नहीं आयी थी।

इस संबंध में मंगलौर पुलिस थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, घटना दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर लिब्बरहेड़ी क्षेत्र में एक मिल के पास हुई। सामने आए एक वीडियो में दिखाई दे रहा है कि करीब 12 कांवड़ियों का यह समूह ई-रिक्शा चालक और उसके वाहन पर डंडों से हमला कर रहा है जबकि पुलिस के जवान उन्हें शांत कराने का प्रयास कर रहे हैं।

करंट लगने से छात्रा की मौत पर मंत्री आतिशी के सख्त तेवर

» मुख्य सचिव को कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के पटेल नगर में करंट लगने से यूपीएससी की तैयारी कर रही छात्रा की मौत हो गयी थी। घटना पर बिजली मंत्री आतिशी ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने मुख्य सचिव को जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मंत्री आतिशी ने कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट अगले 2 दिनों में देने को कहा।

आतिशी ने मुख्य सचिव से दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर रोक लगाने के लिए नीतिगत सुझाव मांगे हैं। मृतक के परिजनों को सहायता अनुग्रह राशि की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने का भी उन्होंने आदेश दिया। बिजली मंत्री आतिशी ने कहा कि पटेल नगर इलाके की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। करंट लगने से 26

वर्षीय आईएएस अभ्यर्थी की जान चली गई। सरकारी अधिकारियों की लापरवाही और उदासीनता के कारण एक युवा की जान चली गई। ऐसे में मौत के कारण का पता लगाने की जरूरत है। भविष्य में घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए दोषियों पर जिम्मेदारी तय कर कड़ी कारवाई करने की जरूरत है।

नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेगा कर्नाटक

» डीके शिवकुमार ने कहा- बजट में हुई राज्य की अनदेखी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

बेंगलुरु। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कांग्रेस सरकार द्वारा 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने के फैसले का बचाव किया। उन्होंने कहा कि राज्य के साथ केंद्रीय बजट में अनुचित व्यवहार किया गया और उसके हितों की रक्षा नहीं की गई। बता दें कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पहले कहा था कि राज्य की मांगों की केंद्रीय बजट में अनदेखी करने के खिलाफ यह फैसला लिया गया है।

शिवकुमार ने कहा कि जब कोई नीति ही नहीं है तो नीति आयोग की बैठक में शामिल होने का क्या औचित्य है? कर्नाटक के साथ केंद्रीय बजट में अनुचित व्यवहार किया गया है। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री ने

आगे कहा कि राज्य को कोई परियोजना नहीं मिली और उसके हितों की भी रक्षा नहीं की गई। हमने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है और इसके बजाय प्रदर्शन करेंगे। वहीं सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि कर्नाटक की आवश्यकताओं पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में सभी दलों के सांसदों की बैठक बुलाने के मेरे गंभीर प्रयासों के बावजूद, केंद्रीय बजट में हमारे राज्य की मांगों की अनदेखी की गई। उन्होंने कहा कि बैठक में शामिल हुईं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक के लोगों की चिंताओं की अनदेखी की। हमें नहीं लगता कि कर्नाटक वासियों की बात सुनी गई, लिहाजा नीति आयोग की बैठक में शामिल होने का कोई औचित्य नहीं है।

बीजेपी मुद्दे का राजनीतिकरण करना चाहती है : शिवकुमार

इस बीच वृहत बेंगलुरु शासन (जीबीए) विधेयक का भाजपा द्वारा विरोध किए जाने के सवाल पर शिवकुमार ने कहा कि वे मुद्दे का राजनीतिकरण करना चाहते हैं। मैं जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहता हूं, मैंने केवल उसे सदन में रखा है। उन्हें इस पर विस्तृत बहस करने दें और उसके बाद फैसला किया जाएगा। बेंगलुरु का विस्तार अनियंत्रित तरीके से हो रहा है और यहां सुशासन की जरूरत है। कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को प्रस्तावित विधेयक विधानसभा में पेश किया जिसका उद्देश्य नगर निकाय प्रशासन के विकेंद्रीकरण करने के वास्ते अधिकतम 10 नगर निगम बनाना है। विधेयक में जीबीए की स्थापना का प्रस्ताव है, जिसके पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, उपाध्यक्ष बेंगलुरु के प्रभारी मंत्री होंगे तथा सदस्य सचिव ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण के मुख्य आयुक्त होंगे।

भारत को मनाने की जिम्मेदारी आईसीसी की : पीसीबी

» आईसीसी की बैठक में टूर्नामेंट के बजट को मिल चुकी है मंजूरी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

मुंबई। पीसीबी ने बीसीसीआई को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए मनाने का काम आईसीसी पर छोड़ दिया है। दरअसल, माना जा रहा है कि बीसीसीआई सुरक्षा कारणों की वजह से भारतीय खिलाड़ियों को पाकिस्तान नहीं भेजेगी। हालांकि, अब तक बोर्ड की तरफ से इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, कोलंबो में हाल ही में हुई आईसीसी की वार्षिक बैठक में चैंपियंस ट्रॉफी के बजट को मंजूरी दे दी गई, लेकिन कार्यक्रम और प्रारूप पर चर्चा नहीं हुई। इस टूर्नामेंट का आयोजन अगले साल फरवरी और मार्च में होगा।

चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया के पाकिस्तान जाने पर संशय बरकरार

वहीं आईसीसी की बैठक के अलावा पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी ने बीसीसीआई सचिव जय शाह या किसी अन्य बीसीसीआई अधिकारी के साथ कोई औपचारिक बैठक नहीं की लेकिन बैठकों के दौरान नकवी और शाह के बीच बातचीत सौहार्दपूर्ण रही। बीसीसीआई ने हमेशा से कहा है कि पाकिस्तान में क्रिकेट खेलना पूरी तरह से सरकार का फैसला है और यहां तक कि पीसीबी की मेजबानी में हुए 2023 वनडे एशिया कप में भारत ने हाइब्रिड मॉडल के आधार पर अपने सभी मैच श्रीलंका में खेले थे। पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जो मसौदा पेश किया है, उसके अनुसार संभावित सेमीफाइनल और फाइनल सहित भारत के सभी मैच लाहौर में निर्धारित किए गए हैं।

पीसीबी ने तैयार किया मसौदा

पीसीबी के एक सूत्र ने कहा कि पीसीबी ने अब वह कर दिया है जो चैंपियंस ट्रॉफी के मेजबान के रूप में उससे अपेक्षित था। उसने प्रतियोगिता का मसौदा कार्यक्रम और प्रारूप सौंप दिया है तथा प्रतियोगिता के लिए बजट भी सौंप दिया है। उन्होंने कहा कि अब यह आईसीसी पर निर्भर है कि वे चैंपियंस ट्रॉफी के कार्यक्रम को कितनी जल्दी प्रसारित, चर्चा और अंतिम रूप देते हैं। पीसीबी ने भारत के सभी मैचों की मेजबानी लाहौर में करने का सुझाव दिया है जिसमें सेमीफाइनल (अगर भारत क्वालिफाई करता है) और फाइनल भी शामिल है।

यूपी की वजह से भाजपा को नहीं मिला बहुमत : अखिलेश

» बोले- जनता जो चाहती थी, हमने वो ही मुद्दे उठाए

» सपा प्रमुख ने कहा- यूपी में लखनऊ-दिल्ली के बीच चल रहा टसल

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि पूरा देश ऐसे ही परिणाम का इंतजार कर रहा था जो साल 2024 के लोकसभा चुनाव में आएं हैं। उन्होंने दावा किया कि यूपी की वजह से भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में बहुमत नहीं मिला।

सपा प्रमुख ने कहा कि जनता ने हमें सहयोग किया। जहां वो 80 में 80 सीटें हासिल करने का दावा कर रहे थे वहां यूपी की जनता ने उन्हें रोका। जो जनता चाहती थी वह हमने मुद्दे उठाए। लोकसभा क्षेत्र में लोग जिस नेता को चाह रहे थे हमने उसे प्रत्याशी बनाया। परिणाम यह हुआ कि पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में जीते भले हो लेकिन वोट से हार गए।

हमें भाजपा के एमवाई को हराना था

कन्नौज सांसद ने कहा कि यूपी बीजेपी में सिर्फ 2 नेताओं की लड़ाई नहीं है। बल्कि दिल्ली और लखनऊ के बीच टसल है। एक सवाल के जवाब में टिकट वितरण पर अखिलेश ने कहा कि बीजेपी हम पर आरोपी लगाती थी कि हमारे पास केवल एमवाई वोट समीकरण था, लेकिन मुझे बीजेपी के एमवाई (मोदी और योगी) को हराना था इसलिए रणनीति बदली और पीडीए की ओर आगे बढ़े। अखिलेश ने कहा कि हमने आरक्षण, संविधान का मुद्दा उठाया और इसका परिणाम यह हुआ कि जनता हमारे साथ जुड़ी। जो लोग यूपी में 80 की 80 सीटों का सपना देख रहे थे वह इसी राज्य की वजह से बहुमत नहीं हासिल कर सके।

हमने अपने कार्यकर्ताओं को बूथ तक जोड़ा

सपा नेता ने कहा कि बीते कुछ समय से हम चुनाव हार रहे थे। हमारे पास बीजेपी के बराबर संसाधन नहीं है इसलिए हमने अपने कार्यकर्ताओं को बूथ तक जोड़ने का संदेश दिया जिसका परिणाम आज हमारे सामने है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि चुनाव में प्रशासन उनके साथ था। बीजेपी के सहयोगी दल जमीन पर लोगों को भड़का रहे थे।

इरफान सोलंकी की पत्नी होंगी सीसामऊ से सपा प्रत्याशी!

सपा ने कानपुर की सीसामऊ विधानसभा पर होने वाले उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी के नाम की तस्वीर लगभग साफ कर दी है। सपा के राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से कानपुर में ये संदेश पहुंचा दिया गया है कि इस सीट से सपा का कोई और नेता या चेहरा चुनाव नहीं लड़ेगा बल्कि जेल में बंद विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम इस सीट की दावेदार भी हैं और वही प्रत्याशी भी। सभी अटकलों पर कानपुर के सपा जिलाध्यक्ष गजल महमूद ने विराम लगा दिया है। सीसामऊ सीट पर इरफान सोलंकी के जेल जाने के बाद सपा के कई दिग्गज इस सीट से अपना भाग्य आजमाना चाहते थे क्योंकि इस सीट पर लंबे समय से सपा का ही कब्जा रहा है। लेकिन अब सपा जिलाध्यक्ष ने साफ कर दिया उनसे स्वयं अखिलेश यादव ने नसीम सोलंकी का नाम लिया और कहा है की तैयारी में लगो। जिसके बाद अन्य नेताओं की दावेदारी और अटकलें थम गईं।

चार दिन में खत्म हो रहा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का कार्यकाल

» 29 जुलाई 2024 को अपना कार्यकाल पूरा करेंगी गवर्नर

» नए राज्यपाल को लेकर अब तक नहीं शुरू हुई कोई चर्चा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का कार्यकाल 29 जुलाई 2024 को खत्म हो रहा है। आनंदीबेन पटेल पांच साल पहले 29 जुलाई 2019 को यूपी के राज्यपाल का कार्यभार संभाला था। ऐसे में राज्यपाल का कार्यकाल खत्म होने में अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं। हालांकि, अभी तक इस बात की सुगबुगाहट नहीं है कि राज्य का अगला राज्यपाल कौन होगा? सवाल यह भी है कि क्या आनंदीबेन पटेल फिर से यह जिम्मेदारी संभालेंगी या किसी अन्य राज्यपाल को राज्य का प्रभार दिया जाएगा।

इससे पहले आनंदीबेन पटेल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की राज्यपाल रह चुकी हैं। वो साल 1987 में राजनीति में आईं। वो भारतीय जनता पार्टी में राज्य महिला मोर्चा की अध्यक्ष, भाजपा की राज्य इकाई की उपाध्यक्ष, भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की सदस्य सरीखे महत्वपूर्ण पदों पर रहीं। आनंदीबेन पटेल 22 मई 2014 से 7 अगस्त 2016 तक गुजरात राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रहीं।

यूपी में किसी राज्यपाल ने दोबारा नहीं संभाला जिम्मा

उत्तर प्रदेश में अभी तक ऐसा राज्यपाल नहीं रहा है जिसका कार्यकाल दूसरी बार रहा हो। अगर आनंदीबेन पटेल को फिर से यूपी की जिम्मेदारी मिलती हैं तो वह ऐसा करने वाली पहली राज्यपाल होंगी। 2 मई साल 1949 से अब तक राज्य में कुल 24 राज्यपाल रहे चुके हैं। 29 जुलाई को राज्यपाल का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी नई नियुक्ति या किसी को प्रभार दिए जाने तक पद की जिम्मेदारी आनंदीबेन पटेल के पास ही रहेगा। आनंदीबेन पटेल यूपी की पहली महिला राज्यपाल भी हैं।

फोटो: 4पीएम

धरना 26 जून 2024 को राजधानी के पारा इलाके में विजय कुमार की हत्या हो गई थी। मृतक के परिजनों ने जयप्रकाश, उमावती, सरवन व कुलदीप के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन किया। परिजनों का आरोप है कि पारा पुलिस आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।

मायावती ने की नीट प्रणाली को खत्म करने की मांग

» बोलीं- पुरानी व्यवस्था को फिर से किया जाए लागू

» केंद्र मेडिकल की इस अहम परीक्षा को सही से कराने में नाकाम

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। नीट पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट के परीक्षा दोबारा न कराने के आदेश जारी करने के बाद मामले पर सियासत अभी भी जारी है। इसे लेकर अब बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती की प्रतिक्रिया सामने आई हैं। बसपा सुप्रीमो ने इस मामले को लेकर केंद्रीय मेडिकल परीक्षा की प्रक्रिया को खत्म कर पुरानी व्यवस्था को बहाल करने की मांग की है।

नीट पेपर लीक के मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों समेत बसपा सुप्रीमो मायावती भी लगातार सवाल उठा रही हैं। जिसके बाद अब उन्होंने मेडिकल की पुरानी परीक्षा प्रणाली को ही बहाल करने की मांग कर दी है उन्होंने कहा कि जिस तरह से नीट कराने वाली परीक्षा एनटीए पर सवाल उठ रहे हैं वो गंभीर मुद्दा है। इससे लाखों परीक्षार्थी मानसिक पीड़ा झेल रहे हैं।

लाखों परीक्षार्थियों को हुई मानसिक पीड़ा

बसपा सुप्रीमो ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ऑल-इंडिया नीट-यूजी मेडिकल परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर स्वाभाविक तौर पर सड़क से लेकर संसद व सुप्रीम कोर्ट तक में यह मामला गर्माया रहा। अब नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन लाखों परीक्षार्थियों व उनके परिवार वालों को इसको लेकर हुआ दु:ख-दर्द व मानसिक पीड़ा हमेशा सताएगी। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र मेडिकल की इतनी अहम परीक्षा सही से कराने के मामले में देश को आश्वस्त कर पाने में अभी तक विफल है। जो समस्या को और गंभीर बना रहा है। अतः केंद्रीयकृत मेडिकल नीट यूजी-पीजी परीक्षाओं को समाप्त कर इसके लिए पुनः पुरानी व्यवस्था क्यों न बहाल हो, जैसा कि कई राज्य सरकारों की मांग है।

'दिल्ली की कानून-व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त'

संजय सिंह बोले- यहां होते हैं गैंगवार, पीएम, गृहमंत्री और एलजी हैं इसके जिम्मेदार

» नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेगी आप

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। यहां गैंगवार होते हैं। इसके लिए पूरी तरह से प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के एलजी जिम्मेदार हैं। ये लोग दिल्ली पुलिस को और मजबूत बनाने की जगह उसे कमजोर कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस के बजट को 531 करोड़ रुपये कम कर दिया है। दिल्ली की कानून व्यवस्था के प्रति केंद्र सरकार गंभीर नहीं है। उन्हें दिल्ली की चिंता नहीं है।

नीति आयोग की बैठक का कोई मतलब नहीं

आप नेता ने नीति आयोग की बैठक को लेकर भी केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों द्वारा शासित राज्यों के लिए जब कोई नीति और बजट में प्रावधान नहीं है तो नीति आयोग की बैठक का मतलब क्या है। इसलिए विपक्षी राज्य हैं उन्होंने बैठक का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। दिल्ली और पंजाब को तो खासतौर से इग्नोर किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली की वित्तमंत्री मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर जा सकती थीं, लेकिन उन्होंने भी बैठक का बहिष्कार किया है। वहीं आम आदमी पार्टी से सासंद मलविंदर सिंह कंग ने भी नीति आयोग की बैठक को लेकर सवाल खड़ा किया है।

इसके अलावा संजय सिंह ने बजट को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने बजट में दिल्ली और पंजाब की उपेक्षा की है और इसी वजह से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की प्रतिनिधि के रूप में वित्तमंत्री आतिशी भी इस बैठक में शामिल नहीं होंगी।

अगस्त में होगी यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की तारीखों का ऐलान हो गया है। पुलिस की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के 60244 पदों पर सीधी भर्ती-2023 की लिखित परीक्षा दिनांक 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त 2024 को आयोजित कराने का निर्णय लिया गया है।

बताया गया कि अवगत कराना है कि यह परीक्षा पूर्व में निरस्त कर दी गयी थी। प्रदेश के सीएम द्वारा निर्देशित किया गया था कि यह परीक्षा 06 माह के अन्दर शुचिता एवं पारदर्शिता के उच्चतम मानकों को दृष्टिगत रखते हुए फिर आयोजित करायी जाए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस परीक्षा को एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत शुधितापूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से उच्चतम मानकों के अनुसार आयोजित करने की प्रतिबद्धता के कम में यह कार्यकम घोषित किया गया है।

स्वामी 4 पीएम न्यूज नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक संजय शर्मा द्वारा आस्था प्रिंटर्स, 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से मुद्रित एवं 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से प्रकाशित। संपादक - संजय शर्मा, विधि सलाहकार: सत्यप्रकाश श्रीवास्तव, मोहम्मद हैदर, वित्तीय सलाहकार: संदीप बंसल, कार्टूनिस्ट: हसन जैदी, दूरभाष: 0522- 4078371 | Email: daily4pm@gmail.com | website: www.4pm.co.in
RNI-UPHIN/2015/62233 डाक पंजी. सं- SSP/LW/NP-495/2018-2020 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय के अधीन ही होंगे।